†[प्रतिरक्षा उपमन्त्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । चूंकि सशस्त्र सेवाबल के मुख्य कार्यालयों और मान्य संस्थाओं के कर्मचारीगण की अपनी अलग असैनिक सेवा चाहते थे, सशस्त्र सेवा बल के मुख्य कार्यालय, केन्द्रीय मंत्रालयों की सेवा के बनने पर, उस में शामिल नहीं हुए थे ।]

श्री नवाबसिंह चौहान : हालांकि यह शरीक नहीं हुये थे, लेकिन क्या मोटे तरीके से उसके जो कायदे कानून हैं, उन पर अमल किया जाता है ?

SHRI K. RAGHURAMAIAH: The rules and regulations governing the Armed Forces Headquarters are different from those governing the Central Secretariat Service.

श्री नवाबसिंह चौहान : क्या वजह है कि दूसरी मिनिस्ट्रीज से इनके रूल्स को, जहां तक अप्लीकेशन का ताल्लुक है, अलग रखा गया है ?

SHRI K. RAGHURAMAIAH: Sir, actually, in 1949, when the Central Secretariat Service Scheme was initiated, there were consultations, and again in 1950, but then the representatives of the Staff Associations of the Armed Forces Headquarters did not want to join the Central Secretariat Service Scheme. Since then there have been representations both for integration and against, and Government have been very anxiously considering for quite a long period as to whether anything can be done in th.e matter, and the matter is still under very active consideration.

अस्थायी पदों का स्थायी किया जाना

*२८३. **श्री नवाबसिंह चौहान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने १९५२ में सिद्धांत रूप में यह स्वीकार किया था कि ८० प्रतिशत अस्थायी पदों को स्थायी कर दिया जावे ;

(ख) यदि हां, तो किस किस मंत्रालय ने द्वितीय वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने से पूर्व इस पर अमल किया और किस किस ने नहीं ; और

(ग) जिन मंत्रालयों ने इस पर अमल नहीं किया, क्या उन के अस्थायी कर्मचारियों के पद पेंशन के लिये १९५२ से स्थायी जैसे माने जायेंगे ?

t[ ] Hindi Translation.

CONVERSION OF TEMPORARY POSTS INTO PERMANENT ONES

*283. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government 'of India had agreed in prir*-ciple in 1952 that eighty per cent, of the temporary posts should be converted into permanent posts;

(b) if so, which of the Ministries had acted accordingly before the submission of the Second Pay Commission's Report and which of the Ministries had not acted; and

(c) whether the posts 'of temporary employees working in those Ministries who had not acted accordingly will be considered as permanent for the purposes of pension from 1952?]

वित्त उपमन्त्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) (क) १९५१ में आदेश जारी किये गये थे कि नीचे दी गयी श्रेणियों के पदों को, जिनकी जरूरत स्थायी ढंग से काम के लिए है, स्थायी कर दिया जाये :—

(१) अधीनस्थ (सबोर्डिनेट) कार्यालयों में पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के ८० प्रतिशत अस्थायी पद ;

(२) सचिवालय (सेक्रेटेरिएट), संलग्न (अटैच्ड) और अधीनस्थ कार्यालयों में

t[ ] English translation.

चौथी श्रेणी के ५० प्रतिशत अस्थायी पद, बशर्ते कि पहली जनवरी १९५२ को उन पदों को बने ५ साल हो गये हों ।

(ख) १९५६-५७ में स्थिति की जो समीक्षा की गयी उससे पता चला कि लगभग सभी मंत्रालयों ने इन आदेशों पर अमल किया है । लेकिन कुछ संगठनों में अस्थायी पदों को स्थायी नहीं किया गया, क्योंकि या तो उन संगठनों का काम अस्थायी ढंग का था या उनकी स्थायी आवश्यकताओं पर विचार किया जा रहा था ।

(ग) जी, नहीं ।

|[THE DEPUTY MINISTER OF FINANCE (SHRIMATI TARKESHWARI SINHA): (a) Orders were issued in 1951 that the following categories of posts which were required for Work of a permanent nature may be converted into permanent ones: —

(i) Eighty per cent, of the temporary posts in classes I, II, and III in the subordinate offices;

i) 50 per cent, of the temporary posts in class IV in the Secretariat, Attached, and subordinate offices, provided they had been in existence for a period of 5 years on 1st January, 1952.

(b) A review of the position made in 1956-57 revealed that, by and large, all the Ministries had acted on the orders. In some Organisations, however, temporary posts were not converted into permanent ones either because the work of the Organisations themselves was of a temporary nature or because an assessment of their permanent requirements was under contemplation.

(c) No, Sir.]

श्री नवाबसिंह चौहान : कुछ ऐसी कैटेगरीज बताई हैं जिनको किन्हीं कारणों से परमानेंट नहीं किया जा सका । उनमें से बहुत से लोग रिटायर भी हो गये हैं जिसकी वजह से उनको बहुत नुकसान हुआ है । अगर उनको उस वक्त पर्मानेंट कर दिया जाता तो उनको जो पेंशनरी राइट्स हैं उसमें फायदा होता । तो क्या इसमें कुछ तरमीम की जायगी ? हालांकि वे रिटायर हो गये हैं लेकिन तब भी क्या उनको इस आर्डर से कुछ फायदा पहुंचाने की कोशिश की जायगी ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जिस दिन इस मंत्रालय से आर्डर निकला है उस दिन से तो उस पर कार्यवाही नहीं होती है, बल्कि जिस दिन से, या जिस तारीख से आर्डर लागू होता है, उसी दिन से या उसी तारीख से उस पर कार्यवाही करने के लिये, उसको लागू करने के लिये नियम बनाये जाते हैं । जैसा कि मैंने अभी अपने जवाब में बताया कि कुछ कुछ कारण ऐसे थे जिनको मद्देनज़र रखते हुए कुछ मंत्रालयों में उनको पर्मानेंट नहीं किया जा सका, जैसे कि वे पोस्ट्स टेम्पोरैरी किस्म की थीं, अस्थायी थीं या उनके बारे में स्पेशल रिआर्गेनाइज़ेशन यूनिट की कुछ जांच-पड़ताल चल रही थी कि कितनी पर्मानेंट पोस्ट्स की जरूरत है और जिन पोस्ट्स की जरूरत न हो उनको नहीं रखा जाय । जैसे कि मिनिस्ट्री आफ रिहैबिलिटेशन, सेंट्रल ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन वगैरह है । मिनिस्ट्री आफ ला में भी कुछ ऐसे पद थे और मिनिस्ट्री आफ डिफेंस में भी कुछ ऐसे पद थे, जिनके बारे में ऐसी जांच पड़ताल चल रही थी । तो कुछ पद अस्थायी ज़रूर रख दिये गये हैं और उसका कारण यह है ।

श्री नवाबसिंह चौहान : जब सेकेंड पे कमीशन की रिपोर्ट निकली थी तब ऐलान किया गया था कि पहली अप्रैल सन १९५६ ई० को जो लोग टेम्पोरैरी थे और जो उसके पहले तीन साल काम कर चुके थे, उनको पर्मानेंट कर दिया जायगा, लेकिन इस तरीके से पर्मानेंट करने के लिये जो इनक्रीज्ड कैडर

+ [ ] English translation.

कांस्टीट्यूट किया गया वह पहली अप्रैल सन १९५९ ई० में कांस्टीट्यूट किया गया। अगर वह पहले कांस्टीट्यूट हो जाता तो जो रिटायर हो गये हैं उनको भी फायदा हो जाता और वे पर्मानेंट हो जाते। तो ऐसे लोग जो कि-रिटायर हो गये है और जिनको नुकसान हो गया है, उनको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से कुछ फायदा देने की कोशिश सरकार करेगी या नहीं ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस बारे में माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी है क्योंकि जिस दिन पे कमीशन का आदेश निकला उसी समय हमारे मंत्रालय से भी यह ऐलान जारी किया गया कि उनको पर्मानेंट कर दिया जायेगा। तीन साल तक जिन्होंने काम किया है उन में से ८० प्रतिशत को पर्मानेंट किया जाय और अगर उनको पर्मानेंट किया गया तो वह तीन साल तक की सर्विस चाहे वह टेम्पोरैरी पोस्ट पर हो या क्वासी-पर्मानेंट पोस्ट पर हो, जहां तक पेंशन का ताल्लुक है, वह सब उसके लिये इकरार कर ली जायगी। उसमें किसी तरह का डिसक्वालिफिकेशन नहीं आता है।

SHRIMATI SAVITRY DEVI NIGAM: May I know, Sir, if the hon. Minister is aware that in spite of the fact that the office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is in existence for the last ten years the workers and officers working in that office have not been made permanent?

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA: Sir, I have already given some of the names. If I go into details, it will take a very long time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: From their very nature they are temporary.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA: I may add, Sir, that certain posts are by their very nature temporary. There are certain posts which can be made permanent. They "have been in existence for a number of years. As a Special Reorganisation Unit was going into the whole question of economy of the administration, it was left to them and they have been going on, discussing and making deliberation on that. Actually, according to requirements, we have been making them permanent if the need is there.

PANDIT HRIDAY NATH KUNZRU: Cannot Shri Datar give us a more satisfactory reply?

(No *reply.)*

SHRIMATI T. NALLAMUTHU RAMA-MURTI; May I have a clarification,, Sir? The hon. Deputy Minister said that temporary posts of Class IV employees continuing for five years would be converted into permanent posts. May I kn'ow, Sir, whether it refers to continuous service for five years, in succession, or it also refers to interrupted service totalling five yeats?

SHRIMATI TARKESHWAR! SINHA: So far as the five-year business is concerned, it refers to the orders issued in 1951. After that the Second Pay Commission issued directions in 1960, and we have sent a circular to the respective departments saying that the persons who have worked in the department on a temporary basis or on a quasi-permanent basis for three years should be made permanent as far as possible.

DR. R. B. GOUR: In view of the fact that many of the employees have put in years of service in a temporary capacity in temporary departments, is it not the policy of the Government to absorb them as far as p'ossible as and when permanent vacancies arise in other departments?

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA: It is already the policy of the Government to absorb as many people as it can conventiently.

PANDIT HRIDAY NATH KUNZRU: Has Shri Datar nothing to say with regard to the failure of the Government to make any of the posts in the office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes permanent?

SHRI B. N. DATAR; If the hon. Member had brought it to my notice, I would have certainly looked into the matter and given him the fullest reply. Now, since he wants me to say something, may I point out in this respect that we are governed by a circular of the Finance Ministry according to which 80 per cent, of the posts that are likely to be made permanent should be immediately confirmed? We are following that policy.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, that has been answered.

*284. *[The questioner (Shri Babu-bhai Chinai) was absent. For answer,* vide *col.* 1319-20 infra.]

FINDING OF RUINS OF AN HISTORIC PALACE NEAR ALLAHABAD

*285. SHRI JUGAL KISHORE: Will the Minister of SCIENTIFIC RESEARCH AND CULTURAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the ruins of an historic palace were found near Allahabad" in Uttar Pradesh on or about 15th June, 1961;

(b) if so, how old the palace is and what is its history; and

(c) how the palace was discovered and what are its details?

THE MINISTER OF SCIENTIFIC RESEARCH AND CULTURAL AFFAIRS (SHRI HUMAYUN KABIR): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

*286. *[The questioner* (Shri P. *Ramamurti) was absent. For answer* , vide *col.* 1320 infra.]

CRACKER EXPLOSIONS IN A MOSQUE IN CHANDNI CHOWK, DELHI

*287. SHRI FARIDUL HAQ ANSARI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the answer given to Starred Question No. 218 in the Rajya Sabha 'on the 3rd May, 1961 and state:

(a) whether the investigations in respect of two cases of cracker explosions in a mosque in Chandni Chowk, Delhi have since been completed; and

(b) if so, what has been the result of the investigations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI B. N. DATAR) : (a) and (b) There was one cracker explosion in the courtyard of the Fatehpuri Mosque, Delhi, on the 10th March, 1961. The incident has been thoroughly investigated but it has not been possible to trace the culprits.

SHRI FARIDUL HAQ ANSARI: Sir, it was reported in the press, and as mentioned in the Starred Question No. 218 on the 3rd May, 1961, that there have been two incidents of cracker explosion in that mosque. May I know, Sir, whether both these incidents have been investigated or only one has been investigated?

SHRI B. N. DATAR: Sir, so far as the incident in this m'osque is concerned,—I speak subject to correction —there was only one incident at 8-20 P.M. on 10th March, 1961.

आचार्य रघुबीर : दीवान हाल में दो दिन हुए या तीन दिन हुए जो क्रैकर फटा उसके बारे में मंत्री महोदय कुछ सूचना देंगे कि वह कौन व्यक्ति था जिसने ऐसा किया ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is a different question.